



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जनता जल योजना व पीएचईडी पर बकाया राशि 31 दिसम्बर तक जमा करावें
— भास्कर ए. सावंत

जयपुर, 18 दिसम्बर। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने जनता जल योजना में एवं पीएचईडी पर बिजली बिलों एवं अण्डरटेकिंग की सर्किलवार बकाया राशि को 31 दिसम्बर तक जमा कराने के लिए पीएचईडी एवं विभिन्न जिला परिषदों के सीईओ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। आज आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं अधीक्षण अभियन्ता सहित विभिन्न जिलों में जन सेवा केन्द्रों पर विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ ही जिला परिषदों के सीईओ एवं पीएचईडी के अधीक्षण अभियन्ता भी उपस्थित रहे।

श्री सावंत ने 18 दिसम्बर को विद्युत भवन से प्रथम बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की बकाया राशि के बारे में विवादित प्रकरणों की कारण सहित सूची तैयार कर उसका विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को बताया कि जनवरी माह से जनता जल योजना के कनेक्शनों पर प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे, इसके लिए भी पंचायत राज विभाग के अधिकारी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही कर लें।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पीएचईडी से बिजली बिलों एवं अण्डरटेकिंग की बकाया राशि, जनता जल योजना पर बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली की प्रगति की समीक्षा सहित डिस्कॉम की योजनाओं के बारे में 18 नवम्बर को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के क्रम में निगम के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। 33 केवी/11 केवी फीडर्स पर ट्रिपिंग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए ट्रिपिंग बन्द होनी चाहिए और फिर भी यदि ट्रिपिंग आ रही है तो उसका कारण ढूँढकर उसे तुरन्त दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके साथ ही खराब मीटरों को बदलने, केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर की सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कॉल सेन्टर पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की विजीलेन्स चेकिंग, उपभोक्ताओं के मोबाईल नम्बर कलक्शन, रबी की फसल के लिए कृषि में ब्लॉक आवर्स में बिजली आपूर्ति, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजना एवं कृषि कनेक्शन जारी करने सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वीडियो कान्फ्रेंस में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी, अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस), मुख्य लेखाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जिसमें ब्लॉक लेवल तक सभी सहायक अभियन्ता व लेखाकार उपस्थित रहे।